सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-7 7 से 21 अप्रैल, 2013 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

केन्द्रीय बजट 2013-14

चेहरा मासूम, चरित्र भयावह आक्रामक

आम तौर पर फरवरी के अंत में, केन्द्रीय बजट को पेश किए जाने के दिन से बहुत पहले ही, इसको केन्द्र करके मीडिया हो हल्ला मचाना शुरू कर देता है। बेरहम पूँजीवादी शोषण की चक्की में पिसते आम लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि यह बजटीय कवायद राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। जिन्होंने पैसा कमाने और विशेषज्ञ टीकाकारों के तमगे की खातिर खुद को दमनकारी शासक एकाधिकारी पूँजीपतियों के पास गिरवी रख दिया है ऐसे बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों का एक दल यह स्थापित करने के लिए सक्रिय हो जाता है कि औद्योगिक घरानों, बड़े व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरत ही अर्थव्यवस्था की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करके ही विकास को बढ़ाया जा सकता है, जबकि अभागे आम लोगों की निरन्तर बढ़ती तकलीफों और मुसीबतों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम को लोकलुभावन करार दिया जाता है जो तात्कालिक राजनैतिक फायदों के लिए आर्थिक अनिवार्यताओं को निरस्त करने और सुधारों पर लगाम लगाने की इजाजत देता है। यह सच है कि उत्पीड़ित करोड़ों लोगों के सामने इस षड़यन्त्र का अधिकाधिक पर्दाफाश होता जा रहा है जो देखते हैं कि प्रत्येक बजट के बाद उनकी हालत और भी बदतर हुई है चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार में रहा हो। लेकिन यह पर्दाफाश उल्टे उनमें और अधिक निराशा, हताशा और उदासीनता, एक तरह की नासमझ प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। जबकि होना चाहिए था कि सच सामने आ जाता और वे इस साजिश को नाकाम करने के वास्ते वांछित कार्रवाई के लिए प्रेरित हो जाते। इसलिए, यह जरूरी है कि बजट के कुछ बुनियादी पहलुओं पर फोकस करने के लिए तमाम भारी भरकम मुहावरों और जुमलों को नजरअंदाज

पटना में केन्द्रीय आम बजट का विरोध करते हुए एसयूसीआई(सी) के कार्यकर्ता

किया जाए ताकि लोगों को यह समझने में मदद दी जा सके कि किस प्रकार बुर्जुआ शासन तन्त्र उनके जीवन के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है।

विकास के झूठे दावे

जैसी कि परम्परा है बजट पेश होने से पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है। सर्वेक्षण से प्रत्याशा की जाती है कि यह विगत वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की असल उपलब्धियों की एक झलक पेश करेगा और अगले वर्ष के लिए रोड मेप क्या होना चाहिए इसे इंगित करेगा। इस साल ऐसा लगेगा कि सभी फ्रण्टों पर दृष्टिगोचर गिरावट को स्वीकार करने के बाद सर्वेक्षण ने भविष्य की एक सुनहरी तस्वीर पेश की है मानो खुशहाली के दिन लौट रहे हैं। इसके अनुसार जीडीपी वृद्धि दर जो 2009-10 में 9.3 प्रतिशत थी वह 2012-13 में घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई है, अब फिर से बढ़कर 2013-14 में 6.1% और 6.7% के बीच हो जाएगी, थोक मूल्य मुद्रास्फीति मार्च तक 6.2-6.6% तक गिर जाएगी बावजूद इसके कि डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और रेल किराये और माल भाड़े की दरों में वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि, सर्वेक्षण ने कोई भेद नहीं खोला है कि इस अति उत्साह का आधार क्या है।

यह बता देना अति महत्वपूर्ण है कि बुर्जुआ अर्थशास्त्री हमेशा जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के आंकड़ों को आर्थिक विकास के पैमाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पूँजीवाद में जहाँ गरीबों और सर्वहाराओं की भारी संख्या को वंचित करके और कंगाल बनाते हुए चन्द अमीरों के हाथों में अधिकतर धन-सम्पदा संचित हो गई है, जीडीपी आर्थिक प्रगति का कोई सूचक नहीं हो सकता है क्योंकि यह बढ़ी हुई धन-सम्पदा के वितरण को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। तब असल सूचक क्या होना चाहिए? निश्चित ही सूचक यह होना चाहिए कि कुल जनसंख्या के जीवन का सामान्य स्तर ऊँचा उठ रहा है या नहीं। क्या ऐसा हो रहा है? 'नहीं' कहने के लिए अर्थशास्त्र के किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, ''किसी भी पैमाने से कतई नहीं हो रहा है।'' सरकार द्वारा स्थापित अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 77% लोग बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। लेकिन योजना आयोग और प्रधानमंत्री सलाहकार बोर्ड में बैठे विदेशों में प्रशिक्षित अर्थशास्त्रियों ने मनगढ़ंत प्रस्थापनाओं और शब्दों की बाजीगरी से इस मुँह बोलती सच्चाई को छिपाने के अपने प्रयास में दावा किया है कि वे लोग जो शहरो में 32 रुपये और गाँवों में 26 रुपये रोजाना खर्च करने की हैसियत रखते हैं उन्हें गरीब नहीं माना जा सकता है और इस तरह काफी हद तक गरीबी को कम कर दिया गया है। लेकिन हर किसी ने इस हास्यास्पद मापदण्ड की खिल्ली उड़ाई है और गरीबी के खिलाफ इन योद्धाओं(!) के जले पर नमक छिड़कते हुए ह्यूमन डेवलपमेण्ट रिपोर्ट 2011 का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया है कि भारत की एचडीआई रैंकिंग और भी गिरकर 187 देशों में 134वें

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रभाकरण के बेटे बालाचन्द्रन की हत्या सुनियोजित—एसयूसीआई (सी)

श्रीलंका में एलटीटीई के दिवंगत नेता प्रभाकरण के 12 वर्षीय बेटे बालाचन्द्रन की श्रीलंकाई सेना द्वारा नृशंस ढंग से की गई हत्या की निन्दा करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 22 मार्च को जारी प्रैस बयान में कहा,

हाल ही में इंग्लैण्ड के टीवी चैनल-4 द्वारा टेलिकास्ट की गई एक डोक्यूमेण्टरी में श्रीलंकाई सेना द्वारा 2009 में एलटीटीई के दिवंगत नेता वी प्रभाकरण के 12 वर्षीय बेटे बालाचन्द्रन की हिरासत में बर्बरता से ठण्डे दिमाग से की गई हत्या की तस्वीर दिखाई गई। इस बर्बर हत्याकाण्ड की हम कड़ी निन्दा करते हैं। सच से उठा पर्दा यह भी दिखाता है कि एलटीटीई के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक क्रोस-फायर में उनकी मौत होने की श्रीलंकाई सेना द्वारा पूर्वकथित कहानी कैसे एक बेबुनियाद झूठी कहानी थी। साफ जाहिर है कि यह हत्याकाण्ड इण्टरनेशनल चार्टर में समावेशित मानव अधिकारों का न केवल सरासर उल्लंघन है बल्कि महज बदले की भावना से की गई एक सुनियोजित हत्या के सिवाय और कुछ नहीं है।

श्रीलंका लम्बे अर्से से साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा शासक श्रीलंकाई बुर्जुआ के साथ मिलीभगत से करवाये गये, लगातार शह और पैसे की सहायता देकर भड़काए गए निकृष्ट अंधराष्ट्रीवादी नस्लीय विद्वेष और दंगे-फसाद से ग्रसित है। नतीजतन हजारों बेकसूर लोगों की जान चली गई है और कई हजार लोगों को अपनी मातृभूमि से बेदखल कर दिया है।

साम्राज्यवादी चरित्र विकसित कर चुका भारतीय बुर्जुआ वर्ग भी इस उपमहाद्वीप पर दुर्जेय महाशक्ति के तौर पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिए प्रयासरत है। वह भी अपने निहित स्वार्थ में इस भ्रातृघाती खून-खराबे को लगातार चलते रहने में आग में घी डालने का काम करता आया है। दूसरी तरफ विश्व साम्राज्यवाद के सरगने अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथ इराक और अफगानिस्तान में मारे गए लाखों लाख निरीह नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं और दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करने, भ्रातृघाती झगड़े-फसादों व नस्लीय मुठभेड़ों को अंजाम देने और दूसरों की सम्प्रभुता को पैरों तले रोंदने में वह सिद्धहस्त है। वही अमेरिका मानवाधिकार उल्लंघन के लिए श्रीलंका सरकार को सेंसर करने का प्रस्ताव हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में लाया है। जाहिर है कि वह अपनी काली करतूतों की ओर से दुनिया के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ फेरने और श्रीलंकाई अथोरिटियों से कुछ रियायतें और फायदे झटक लेने के लिए इस पर दबाव डालने के एक रणकौशल के तौर पर इस्तेमाल करने के मद्देनजर ही यह प्रस्ताव लाया है। हमारा दृढ़मत है कि श्रीलंका में नस्लीय झगड़े-फसाद की समस्या तमिल या सिंहलीय अंधराष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देने से हल नहीं होगी बल्कि इससे तो यह और भी घनघोर हो जाएगी। इसे सभी संकीर्ण तबकाती नजरियों से उपर उठकर सही समझ रखने वाले धर्मनिरपेक्ष जनवादी ख्यालात वाले लोगों की निश्चित पहलकदमी के जरिए हल किए जाने की जरूरत है। हम पीड़ित श्रीलंकाई जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं और इन तमिल व सिंहली दोनों प्रधान नस्लीय आबादियों के बीच दरार डालने की श्रीलंकाई बुर्जुआ सरकार और विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों की घिनौनी चालबाजी के खिलाफ संयुक्त रूप से उठ खड़े होने, बालाचन्द्रन की नृशंस हत्या की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी उदाहरणमूलक सजा देने की मांग करने का उनसे आह्वान करते हैं।

डीजल मूल्य वृद्धि का एसयूसीआई (सी) द्वारा विरोध

डीजल की मूल्य वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 23 मार्च को जारी एक प्रैस बयान में कहा,

जैसे कि अन्देशा था, सरकार ने डीजल के मूल्य निर्धारण से सरकारी नियंत्रण धीरे-धीरे कम करते जाने की अपनी घोर जनविरोधी नीति पर चलते हुए वार्षिक बजट पेश करने से ऐन पहले डीजल के खुदरा दाम 43 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इससे आवश्यक चीजों की महंगाई और भी बढ़ जाएगी और सिंचाई के लिए डीजल पम्प इस्तेमाल करने वाले गरीब किसानों का जीना दूभर हो जाएगा। इसके साथ ही यह दाम बढ़ोतरी रेल एवं सड़क यातायात एजेन्सियों को यात्री किराया व माल भाड़ा बढ़ाने का मौका दे देगी। दरअसल, अब यह एक नीति हो जाएगी कि समय-समय पर ईंधन-तेल के दाम मुनाफाखोर तेल कम्पनियों की 'कम वसूली' या 'अण्डर रिकवरी' को कम करने के जाहिराना बहाने से मनमाने ढंग से बढ़ाते जाना और पहले से ही विकराल रूप लेती जा रही महंगाई की मार के मारे आम आदमी की बड़ी भारी दु:ख-तकलीफों का जरा भी ख्याल रखे बिना और भी ज्यादा महंगाई बढ़ा देना। बुर्जुआ वर्ग हित की ताबेदार सरकार की इस घिनौनी कार्रवाई और नीति का हम कड़ा विरोध करते हैं और दुखी-परेशान जनता से इसके खिलाफ उठ खड़े होने और प्रतिवाद करने का आह्वान करते हैं।

केन्द्रीय बजट 2013–14

(पृष्ठ 1 का शेष)

स्थान पर आ गई है। बावजूद इसके कि जीडीपी वृद्धि दर गिर रही है और आम लोगों की बदहाली बढ़ रही है और वित्तमंत्री को भी यह स्वीकार करना ही पड़ा है कि ''विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था'' के रूप में उभरने के लिए उन्हें और उनकी सरकार को ''बहुत से तबकों के लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा'' और वे ''बाध्यकारी न्यायसंगतता के नैतिक मामले'' का प्रत्युत्तर नहीं दे सके। यह सिर्फ इसी बात को प्रदर्शित करता है कि ''इन्क्लूसिव'' मायने सभी तक समृद्धि पहुँचाने वाली आर्थिक वृद्धि के बारे में सरकार के दावे कितने खोखले हैं। इसलिए उनके और उन जैसों के द्वारा अक्सर दिए जाने वाला यह तर्क कि 'उच्च विकास दर से सभी तक समृद्धि पहुँचेगी और टिकाऊ विकास होगा', औंधे मुँह गिर पड़ता है। इस प्रकार बहु-प्रचारित विकास की यह ट्रेजेक्टरी गरीबों और सर्वहाराओं के लिए एक अभिशाप है।

गिरते हुए जीडीपी के बारे में सर्वे द्वारा प्रदत्त व्याख्या भी आँखें खोलने वाली है। यह स्वीकारती है कि खपत में तीव्र गिरावट आई है। इसका मायने यह है कि लोगों की खरीद शक्ति तेजी से गिर रही है। यह पूँजीवाद का नियम है जिसमें उत्पादन लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता का शोषण करते हुए पूँजीपति मालिकों द्वारा अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित किया जाना है। शोषित जनता के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए, उत्पादित सामान बिना बिके रह जाते हैं जिसके चलते पूँजीपतियों का बाजार संकट पैदा होता है। चूँकि, उत्पादन ठप्प हो जाता है, मंदी छा जाती है और उद्योगों के शटर बन्द हो जाते हैं। लाखों को रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। बाजार का सिकुड़ना नए उद्योगों की स्थापना को खारिज करता है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इन सबसे बढ़कर बात यह है कि पूँजीवाद के अटल नियम का अनुसरण करते हुए मंदी या सामानों के लगे अम्बार के बावजूद मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है जो कीमतों में उछाल ला देती है। इन सबका सम्मिलित प्रभाव आम आदमी को बाजार से बाहर धकेल देता है और जिस बाजार संकट के तहत ह्रासोन्मुख मरणासन्न पूँजीवाद हांफ रहा है वह और भी गहरा हो जाता है। ऐसी एक पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के बारे में व्यक्त आशावाद का कुछ मायना होता यदि लोगों की आमदनी बढ़ाने, उन्हें स्थाई आधार पर आवश्यकता-आधारित वेतन के साथ रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया जाता और उनकी खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाते।

सर्वेक्षण और वित्तमंत्री की गलत प्राथमिकता

लेकिन वित्तमंत्री और उनकी सरकार का एजेण्डा बिलकुल अलग है। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, सर्वेक्षण जोर देता है कि भारत को अपने दोहरे घाटे का, वित्तीय घाटे और चालू खाते के घाटे का समाधान करना चाहिए और वित्तमन्त्री के लिए ''अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को वापस पाने की चुनौती है'', ''विदेशी निवेश अति महत्वपूर्ण है'' और ''चालू खाते का घाटा बड़ी चिन्ता का विषय है'', और सिर्फ इतना ही नहीं कि पीड़ित देशवासियों को आधारभूत राहत तक की पेशकश नहीं की गई बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत उपलब्ध है उसे भी छीना जा रहा है। बजट की दिशा भी इसी लक्ष्य की ओर है। चालू खाते के घाटे मसलन निर्यात से बढ़कर आयात का मुद्दा लें। व्याख्या की जा रही है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से विदेशी बाजार में भारतीय सामानों की मांग घट रही है जबकि बहुत से क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन का अभाव आयात को आगे बढ़ा रहा है। रुपए की कीमत में आई गिरावट की वजह से (यानी एक अमेरिकी डॉलर या यूरो के समतुल्य ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं जिससे भारतीय सामानों का आयात करने वाला कम डॉलर या यूरो खर्च करके ज्यादा सामान हासिल कर सकता है) निर्यात में वस्तुतः कोई बढ़ोतरी नहीं है। पहले कारण की वजह व्यवस्था से उपजा विश्व पूँजीवाद का अनुलंघनीय संकट है जिसका शासक भारतीय पूँजीपति भी अभिन्न हिस्सा है। दूसरा कारण जो सामने रखा गया है वह पूरी तरह सच नहीं है। ऐसे बहुत से सामान हैं जैसे चीनी, गेहूँ, चावल, दालें और प्याज भी जो सुपर-मुनाफा कमाने के लिए विदेशी बाजार का दौरा करते हैं और फिर वही सामान आयात रूट के माध्यम से पुनः घरेलू बाजार में लौट आता है और ऊँचे दामों पर बेचा जाता है। मुख्य सवाल है येन-केन-प्रकारेण अधिकतम मुनाफा बटोरना।

दूसरे, चूँकि निर्यात रूट के माध्यम से विदेशी मुद्रा का आगमन नहीं हो रहा है इसलिए सरकार इसे दूसरे रास्तों के माध्यम से बढ़ाने की बदहवासी में है जैसे भारतीय पूँजी बाजार में (आम तौर पर शेयर बाजार के रूप में जाना जाता है) विदेशी निवेश को सुगम बनाना और खुदरा व्यापार, बैंकिंग, बीमा और यहाँ तक कि रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सीधे-विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत देना। इस उद्देश्य के साथ इस बजट ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए कई कदमों की घोषणा भी की है जैसा कि इसकी धारा 95 में व्याख्यायित है। वित्तमंत्री कहते हैं, ''सेबी (सिक्योरिटीज़ एण्ड एक्सचैंज बोर्ड ऑफ इण्डिया) प्रक्रिया को सरल बनाएगा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए एक समान पंजीकरण और अन्य तौर तरीके सुझाएगा।'' पेन्शन फण्ड को एफडीआई के लिए खोल देना और पूँजी बाजार की मनमर्जी के आगे पेन्शन फण्ड को पूरी तरह खुला छोड़ देने का उद्देश्य भी बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हासिल करना है। इसके अलावा सट्टेबाजी के धंधे को और भी धन मुहैया करा देना है। इसके अतिरिक्त, पूँजी बाजार सट्टेबाजी को तेज करने के लिए वित्तमंत्री ने कुछ अन्य कदमों की घोषणा भी की है। इनमें महत्वपूर्ण हैं सामानों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग (विभिन्न सामानों के मूल्य में उतार चढ़ाव पर एक प्रकार की सट्टेबाजी) को ''गैर-सट्टेबाजी लेनदेन'' के रूप में देखना और कुछ टैक्स लाभों के लिए पात्रता हासिल कर लेना। जाहिर है कि गैर-नुकसानदेह लगने वाले इस कदम के व्यापक दुष्परिणाम होंगे। टैक्स छूटें हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में बढ़ी हुई सट्टेबाजी आवश्यक वस्तुओं के दामों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और इस प्रकार जहाँ सट्टेबाजों की मौज हो जाएगी वहीं लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। अन्यतम मार्क्सवादी चिन्तनकार और हमारी पार्टी एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर अपने पिछले कई लेखों में हमने दिखाया था कि आज संकटग्रस्त पूँजीवाद उत्पादक निवेश को गैर-मुनाफे का कारोबार पाकर, अन्य चीजों के साथ-साथ, अतिरिक्त पूँजी को मुनाफा कमाने के लिए सट्टेबाजी और सूदखोरी की तरफ अधिकाधिक मोड़ रहा है। यह इस बजट में भी साफ उजागर है। सट्टेबाजी के अतिरिक्त, 25 लाख रुपए तक के हाऊस बिल्डिंग लोन के ब्याज में से टैक्स लाभों के लिए 1 लाख रुपए तक कि अतिरिक्त कटौती की इजाजत देना एक प्रयास है जिससे हाऊसिंग लोन की तरफ ज्यादा बैंक फण्ड छोड़े जाएं और इस प्रकार सूदखोरी रूट के माध्यम से बैंकों को अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिले। साथ ही साथ गृह निर्माण का यह उधार-संचालित जुगाड़ मैटिरियल मार्किट में अस्थाई तेजी ला देगा। लेकिन सर्वविदित है कि सूदखोरी में अतिरिक्त पूँजी के इस निवेश के घटित होने और अर्थव्यवस्था के उधार-संचालित उत्प्रेरण और सट्टेबाजी का नतीजा कितना विनाशकारी रहा जैसा कि सब-प्राइम संकट में देखने को मिला जिसने मात्र कुछ वर्षों पहले न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी साम्राज्यवादी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मजेदार बात यह है कि जब बुर्जुआ दुनिया अपनी अति शक्तिशाली प्रोपेगेण्डा मशीनरी की मदद से यह सिद्ध करने में जुटी थी कि दुनिया भर में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर है तब देश की अर्थव्यवस्था को बाजार उधारी पर चलाने की इस ''आर्थिक दूरदर्शिता'' ने बहुत से यूरोपियन देशों को गहरे सरकारी कर्ज संकट में फंसा दिया। मतलब यह है कि लोन की अदायगी नहीं कर सकने की वजह से पूरा देश दिवालिया हो गया। अमेरिका जिसे साम्राज्यवादी-पूँजीवादी दुनिया का ईन्जन माना जाता है, दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। साथ-साथ वह 16,60,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज के साथ दुनिया का सबसे कर्जवान देश बनने जा रहा है। फिर भी संकटग्रस्त पूँजीवाद के बैगेज-केरियर के रूप में वित्तमंत्री कर्ज पर अर्थव्यवस्था को चलाने के उसी रास्ते का अनुसरण करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सके।

वित्तीय विवेकशीलता (!) और बजट घाटा मैनेजमेण्ट

वित्तमंत्री ने अपनी प्राथमिकता के रूप में एक अन्य क्षेत्र पर जोर दिया है। वह है वित्तीय घाटे को कम करना या दूसरे शब्दों में, सरकार के ज्यादा खर्च और कम आमदनी के बीच के अन्तर को कम करना। वे 2012-13 में वित्तीय घाटा टारगेट को जीडीपी के 5.2% पर रखने में गर्व महसूस कर रहे हैं जो 5.3% के शुरूआती आंकलन से थोड़ा सा कम है। उनका यह दावा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ''भारी वित्तीय घाटे के सामने खर्च को तर्कसंगत करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है'' ...''2011-12 के मुकाबले 2012-13 में लगभग 18% तक सरकारी खर्च में कटौती करना'' इस सफलता को हासिल करने में ''कड़वी दवाई की यह खुराक ...काम करती दिखाई दे रही है।'' जो भी हो, तथ्य यह है कि इन 'कटौतियों' का सबसे बड़ा हिस्सा कुल मूल्य 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा से 92000 करोड़ रुपया, गत वर्ष विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित फण्डों में से जो खर्च नहीं हुए इस बचत के रूप में आए हैं। दूसरे शब्दों में, योजनागत खर्च में भारी पैमाने की कटौती की गई। दूसरी तरफ, सरकार ने 2012-13 में 5.7 लाख करोड़ तक का संभावित टैक्स रिवेन्यू गवां दिया। इसका मुख्य कारण है वित्तीय घाटे में 5,20,925 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मौजूद वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में, आयकर में 4.9% की, सीमा शुल्क में 18.9% की और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 16% की गिरावट हुई है। साफ जाहिर है कि औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारियों को उनके ''नुकसानों'' की (संभावित राजस्व में कमी पढ़ें) भरपाई के लिए प्रचुर मात्रा में दी जाने वाली सौगातों की वजह से यह घाटा हुआ है बावजूद इसके कि इमदादों और खर्च में भारी कटौती की गई जिसका सारा बोझ बदहाल मेहनतकश जनता को वहन करना पड़ता है और कॉरपोरेट घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धन्ना सेठों के प्रति इस अति उदार नजरिए तथा गरीबी के मारे देशवासियों पर 'कठोर फैसले' थोपने में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण ने सलाह दी है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार को टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। (विशेषतौर पर कॉरपोरेट और धन्ना सेठों पर सीधा टैक्स पढ़ें) बल्कि टैक्स दायरे को व्यापक बनाना चाहिए (जिसका मायने है गैर-करदाताओं को टैक्स के दायरे में लाना, उन क्षेत्रों में भी टैक्स थोपना जो अब तक बाहर थे और अंतर्निहित रूप से आम आदमी को निचोड़ने वाले परोक्ष कर पर ज्यादा केन्द्रित करना)। वित्तमंत्री भी इसी रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं लेकिन पैंतरेबाजी के साथ।

उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वे अमीरों के ठाट-बाट और गरीबों को निचोड़ने के रुझान का विरोध करते हैं, इस दिखावे के लिए उन्होंने डरते-डरते 1 करोड़ रुपए का आयकर अदा करने वालों के आयकर पर और देशी-विदशी फर्मों की 10 करोड़ रुपए से अधिक की आयकर योग्य आमदनी पर 10% का सरचार्ज लगाया है। यह विश्वासघात का एक और मामला है। सबसे पहली बात है कि यह अतिरिक्त सरचार्ज सिर्फ एक साल के लिए है और कथित तौर पर 42500 व्यक्ति हैं जो स्वीकारते हैं कि वे 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का टैक्स अदा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में से 315 संसद के सदस्य बताए जाते हैं जो दर्शाता है कि देश की विधायिका में शोषित-उत्पीड़ित जनसाधारण के प्रतिनिधि कैसे हैं। उन पर लगाया गया यह अतिरिक्त टैक्स उनके लिए अति तुच्छ रकम है और टैक्स अदायगी से बचने, झांसा देने के लिए उनके पास अनेक तरीके उपलब्ध हैं, इससे उन्हें जरा भी परेशानी नहीं होने जा रही है। ऐसा ही मामला कॉरपोरेट सैक्टर का है। कोरपोरेट निकायों ने 68000 करोड़ रुपए की सीधी कर रियायतें प्राप्त की हैं लेकिन टैक्सों के रूप में मात्र 22,855 करोड़ रुपये अदा किए हैं जबकि कानूनी दर 32.445% है। इसके अलावा, बड़े देशी-विदेशी कर अदायगी में चूक करने वाले कॉरपोरेटों की मांग की ओर झुकते हुए, वित्तमंत्री ने जीएएआर (जनरल एण्टी एवायडेंस रूल्स) का लागू होना भी 31.03.2016 तक टाल दिया है। उनकी खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार चुनिन्दा सेग्मेण्टों में सीधे करों की मामूली बढ़ोतरी से सिर्फ 13300 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है जो अनुमानित बजट खर्च का मुश्किल से 2% है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संपदा-शुल्क, लोंग टर्म केपिटल गेन्स टैक्स को समाप्त करने और व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर बहुत कम टैक्स रेट के चलते भारतीय अमीर अब भूमण्डलीय अमीरों के सबसे कम टैक्स शुदा सेग्मेण्टों में से एक हैं। इसके अलावा, जबकि सोने की खरीद काले धन को जमा करने का साधन है और सोने का भारी आयात अधिकतर तस्करी के रूप में अति 'चिन्ताजनक' करण्ट एकाउण्ट डेफिसिट के लिए सहायक कारकों में से एक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

देश भर में सम्मानपूर्वक मनाया गया शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरू का शहादत दिवस

गुलाबी बाग (दिल्ली): 31 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का शहादत दिवस एआईडीएसओ की गुलाबी बाग इकाई द्वारा गरिमापूर्वक यहाँ के सेन्ट्रल पार्क में मनाया गया। शुरूआत में शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। सभा के मुख्य वक्ता संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. भास्करानन्द थे। इन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार हम अपने शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। सभा में छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। भगत सिंह के छात्र जीवन पर एक लेख दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रशांत कुमार द्वारा पढ़ा गया और छात्रों को भगतसिंह के छात्र जीवन के बारे में गहराई से बताया गया। सभा का संचालन संगठन की गुलाबी बाग इकाई की अध्यक्ष कॉ. मौसम कुमारी ने किया।

बुराड़ी (दिल्ली): शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के शहादत दिवस के अवसर पर 24 मार्च को एआईडीएसओ की बुराड़ी इकाई द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता व सभा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। निबन्ध का विषय किसी भी क्रान्तिकारियों के जीवन पर था। सभा की शुरूआत क्रान्तिकारियों के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित करने से हुई। सभा को एआईडीएसओ दिल्ली राज्य के अध्यक्ष कॉ. भास्करानन्द ने सम्बोधित किया। उन्होंने छात्रों को इन क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्ष से प्रेरणा लेने की जरूरत दर्शाते हुए शोषणहीन समाज बनाने के उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए छात्र आन्दोलन और भी मजबूत करने पर जोर दिया। इसके पश्चात प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई व उन्हें पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अंत में एआईडीएसओ दिल्ली राज्य कार्यालय सचिव कॉ. राहुल सरकार द्वारा सभी आयोजकों व प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए इस सभा का समापन किया गया। सभा का संचालन एआईडीएसओ की बुराड़ी इकाई की अध्यक्ष कॉ. प्रियंका ने किया।

मुकुंदपुर (दिल्ली): आजादी आंदोलन की गैर-समझौतावादी धारा के महानायक शहीद-ए-आजम भगतसिंह तथा राजगुरू व सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर एआईडीवाईओ की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से 31 मार्च 2013 को दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया।

सभा में शुरूआत में क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति हुई। सभा के मुख्य वक्ता संगठन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉ. दीपक कुमार ने शहीद भगतसिंह के जीवन-संघर्ष का संक्षिप्त परिचय रखते हुए कहा कि शहीद भगतसिंह का संघर्ष आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। सभा को एआईडीवाईओ के संगठन के राज्य अध्यक्ष राकेश कुमार, रामबदन, प्रभाष, अमरजीत, एच.एल. शर्मा, नवीन, ज्योतिभुषण ने भी सम्बोधित किया। सभा का संचालन श्री महेन्द्र (संगठन इंचार्ज, बुराड़ी) ने किया तथा सभा की अध्यक्षता दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रकाश देवी ने की। संगठन द्वारा 23 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न इलाकों में शहीद भगतसिंह के जीवन पर आधारित फोटो व उद्धरण प्रदर्शनी भी लगाई गई।

बृज विहार (गा.बाद): 29 मार्च को क्रान्तिकारी किशोर संगठन, कॉमसोमोल की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव का शहादत दिवस यथोचित सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत शहीदों की तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हुई। सभा की अध्यक्षता एवं एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य एवं कॉमसोमोल के दिल्ली राज्य इंचार्ज कॉ. जी.एस. सिंह ने की। एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. प्रताप सामल ने मुख्य वक्तव्य रखा। उन्होंने शहीदों को याद करने एवं उनसे सीख और प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय छात्र-छात्राओं ने क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील गीत प्रस्तुत किये। कार्यक्रम का संचालन कॉमसोमोल की दिल्ली कोर कमेटी की सदस्य कॉ. श्रेया सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय छात्र-छात्राओं ने ''भगत सिंह लौट के आ'' नामक नाटक की प्रस्तुति की।

लोनी (गा.बाद): 24 मार्च 2013, रविवार को लोनी क्षेत्र के विकास इण्टर कॉलेज में शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू का शहादत दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ तथा महिला संगठन एआईएमएसएस द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत क्रान्तिकारी गीतों एवं कविताओं से हुई। सर्वप्रथम शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पार्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। सभा की अध्यक्षता श्री नित्यानन्द ने की। लोनी क्षेत्र से राकेश, शैलेन्द्र, देवराज, संजय, मोहित, मा. महेश मार्क, शंकर प्रसाद एवं राम अवध राव, अशोक पाण्डेय और भावना ने सभा में अपने विचार प्रस्तुत किए।

सभी वक्ताओं ने वर्तमान समय मे शहीदों की शिक्षाओं का उल्लेख किया। एआईएमएसएस की ओर से श्रीमती बीना विश्वास तथा ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से दिल्ली राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष कॉ. मो. आसिफ ने सभा को सम्बोधित किया। सभा का संचालन एआईडीवाईओ की ओर से कॉ. रवीन्द्र चेतन्य ने किया। एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉ. आर.के. शर्मा के मुख्य वक्तव्य के साथ सभा का समापन हुआ।

फलोदी (राजस्थान): 23 मार्च को ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. फलोदी के तत्वावधान में शहीद-ए-आजम भगतसिंह एवं उनके सहयोद्धा राजगुरु व सुखदेव के बलिदान दिवस पर स्थानीय दीनदयाल उद्यान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षाविद् यागचन्द नागल मुख्य अतिथि थे। शहीद मनीषी यादगार कमेटी के संयोजक छाजूराम रावत भी उपस्थिति रहे।

विचार गोष्ठी में एडवोकेट समस्तदीन मंगलिया, शिक्षक सूर्यप्रकाश जीनगर, जगदीश जयपाल, कमलेश नाहेलिया, तुलसीराम पालीवाल, छात्र जसराज, केसाराम, दिनेश, कृपालसिंह, ईश्वरसिंह, लुणकरण, आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार गोष्ठी का संचालन ऑल इण्डिया डी. एस.ओ. फलोदी की संगीता रावत ने किया। इंकलाब जिन्दाबाद व शहीद भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे, के जोशीले नारो के साथ विचार गोष्ठी का समापन हुआ।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) : 22, 23 मार्च को युवा संगठन आल इंडिया डी. वाई. ओ., छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ. और भूमि अधिग्रहण विरोधी मोर्चा की संयुक्त पहल पर शहीद-ए-आजम भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव के 82वें शहादत दिवस पर दो दिवसीय साइकिल मार्च की शुरूआत सिंगरामऊ प्राथमिक विद्यालय से की गयी। 22 मार्च को साइकिल मार्च को राजा हरपाल सिंह पी. जी. कालेज सिंगरामऊ प्रवक्ता डॉ. रामजीत सिंह ने संगठन का झण्डा दिखाकर रवाना किया। साइकिल मार्च में ए.आई. डी.वाई.ओ. के जिला सचिव कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष कॉ. इन्दु कुमार शुक्ल, जिला कमेटी सदस्य दिनेश कान्त मौर्य, शिवप्रसाद विश्वकर्मा, विजय प्रकाश गुप्त, राकेश निषाद रवीन्द्र पटेल और एआईडीएसओ से जिला सचिव विकास मौर्य, जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार व भूमि अधिग्रहण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष श्री पारसनाथ सिंह (पूर्व प्रधानाचार्य स.ब.इ.कॉ. बदलापुर) भी शामिल थे। बदलापुर तहसील

के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने इन्दिरा चौक पर पुष्प अर्पित किये। स.ब.पी.जी.कॉ. बदलापुर के प्राचार्य डॉ. अखिलेश सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों ने कालेज गेट पर साइकिल मार्च का स्वागत किया। रास्ते में बदलापुर ब्लाक परिसर स्थित शहीद वेदी व धनियामऊ स्थित क्रान्ति स्तम्भ पर माल्यार्पण किया गया। शाम 4 बजे शिवगुलामगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई एक जन सभा में क्षेत्र के सैकड़ो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. जगदीश चन्द्र अस्थाना एडवोकेट ने बतौर मुख्य अतिथि सभा को सम्बोधित किया। अध्यक्षता श्री पारस नाथ सिंह व संचालन कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल ने किया। सभा को कॉ. मिथिलेश कुमार मौर्य राज्य उपाध्यक्ष एआईडीएसओ, कॉ. महेन्द्र कुमार मौर्य जिलाध्यक्ष एआईडीवाईओ व इन्दु कुमार शुक्ल, कॉ. दिनेशकान्त दूबे एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला कमेटी सदस्य ने भी सम्बोधित किया। सभा में वक्ताओं ने बाईपास सड़क के नाम पर किसानों की भूमि केअधिग्रहण, मंहगी शिक्षा, बेतहाशा बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अलीलता, अपसंस्कृति और यौन अपराध जैसी ज्वलन्त समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान भारत में भगत सिंह की क्रांतिकारी व गैर समझौतावादी विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा की। अन्त में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति और भगत सिंह पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। 23 मार्च को 43 कि.मी. का सफर तय करके साइकिल मार्च जौनपुर शहर स्थित भगत सिंह पार्क पहुंचा जहां पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। इसका संचालन का. दिलीप कुमार ने किया। इससे पहले कलेक्ट्रेट स्थित क्रान्ति स्तम्भ व नगर पालिका परिसर स्थित चन्द्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अन्त में जोरदार नारों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

मुरादाबाद (उ.प्र.) : 23 मार्च शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के 82वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 24 मार्च को यहां अम्बेडकर पार्क में एक जनसभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता माहेश्वर तिवारी ने की तथा मुख्य वक्ता थे सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. वी.एन. सिंह। संचालन करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने बताया कि आजादी आन्दोलन के अमर शहीदों के चरित्रों को युवाओं के बीच ले जाने के लिए चलाए जा रहे तीन महीने के युवा जागरण अभियान के अंत में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सभा से पहले रेलवे स्टेशन से शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के चित्रों से सुसज्जित रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुँची। सभा के शुरू में छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने अपने गीत तथा कविताएं प्रस्तुत की। सभा को अन्य स्थानीय वक्ताओं ने भी सम्बोधित किया। हरथला में छेड़छाड़ का शिकार हुई छात्रा द्वारा आत्मदाह करने पर इसमें संलिप्त सपा नेताओं

(शेष पृष्ठ 7 पर)

केन्द्रीय बजट 2013–14

(पृष्ठ 2 का शेष)

है; बजट प्रस्तावों के साथ पेश किया गया फाइनेन्स बिल सोने के कर मुक्त आयात की सीमा में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्शाता है। यह भी बड़ा विचित्र है कि जब अमीरों और समृद्धशालियों द्वारा किया जाने वाला सोने का भारी आयात करण्ट एकाउण्ट डैफिसिट को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है फिर भी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हाल ही में एक आलोचक ने इंगित किया है कि नया कदम लगभग निश्चित ही कोरियर सेवाओं का काम बढ़ा देगा, इससे सोने के आयात में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या तस्करी कम नहीं होगी। दूसरी तरफ व्यापक जनसाधारण को ऐसे वित्तीय कदमों द्वारा बढ़ाए गए परोक्ष करों और बढ़ती मुद्रास्फीति का दंश झेलना पड़ेगा, जरूरत के सामानों के लिए ऊँची कीमतें अदा करने के जरिए।

वर्धित आबंटनों का छल

वित्तमंत्री ने यह डींग हांकते हुए अपनी उपलब्धियों में जोड़ना चाहा है कि कुल बजटीय आबंटनों को 12% तक बढ़ा दिया गया है। सबसे पहली बात है कि यदि अति संयत अनुमान पर मुद्रास्फीति दर को 10% मान लिया जाए तो क्या यह बढ़ोतरी जिसका दावा किया गया है वह अल्पकाल में ही क्षीण नहीं हो जाएगी? इसके अलावा, व्यय करने का मायना कोई आवश्यक नहीं कि परिणाम भी निकले। ऐसा लगता है अत्यधिक आशावादी आंकड़ें दिखाने का यह रुझान अब संस्थागत हो गया है। जैसा पहले जिक्र किया गया है कि आबंटित संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले वर्ष के दौरान इस्तेमाल ही नहीं किया गया। दूसरे, इस बात के स्पष्ट संकेत के बिना कि खर्च में 12% की कथित बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए कैसे अतिरिक्त धन जुटाया जाएगा, संदेह पैदा करता है कि वित्तमंत्री जल्द ही बजट प्रस्तावों को रिवाइज कर सकते हैं और 'बजट के बाहर' रूट के माध्यम से लोगों पर और अधिक बोझ लाद सकते हैं जैसा कि ह्रासोन्मुख मरणासन्न बुर्जुआ संसदीय प्रणाली के इन कर्ताधर्ताओं का चलन बन गया है। साथ-साथ, देश की बैलेंस शीट के आय पक्ष को बढ़ती बाजार उधारियों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के विनिवेश और करेंसी नोट छापने के गुप्त तरीके के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यह भी जोड़ा जा सकता है कि वित्तमंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आरबीआई) संभवत: 2013-14 में केन्द्रीय बजट में दर्ज कुल उधारी 5.79 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए या 64% को अप्रैल-सितम्बर 2013 के दौरान उठाएंगे। विनिवेश का टारगेट कथित तौर पर लगभग 50000 करोड़ रुपए बताया गया है। आम लोगों की कीमत पर संसाधन जुटाने के ये तमाम गुप्त रास्ते अपनाए जाएंगे। सरकारी कर्ज बढ़ता जा रहा है और हालिया आंकड़ों के मुताबिक यह लगभग 4.4 लाख करोड़ रूपए तक पहुँच गया है, गंदी दलदल की तलहटी में रहने वालों सहित प्रत्येक भारतीय पर लगभग 35000 रुपए का कर्ज भार है, चीजें और भी भयावह हो सकती हैं जैसा कि आज पूरे यूरोप में देखा जा रहा है।

मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का नायाब तरीका

बजट के शुरूआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि उनका, ''आर्थिक क्षेत्र दबाव में हैं'' वजह है, अन्य बातों के अलावा ''मुद्रास्फिति काबू में रखने की एक कड़ी मौद्रिक नीति''। लेकिन, बढ़ती मु द्रास्फिति को रोकने के लिए कड़े कदम की बात तो दूर रही, किसी नगण्य कदम का भी आभास नहीं हो रहा है। वित्तमंत्री के मुद्रास्फिति के आंकलन पर कोई कौतुहल से मुस्कुरा ही सकता है। जबकि सर्वे भी बता रहा है ''तीव्र मुद्रास्फिति'' ने ''उपभोग मांग को धीमा कर दिया है'' और घटती विकास दर का मुख्य कारक माना है वहीं वित्तमंत्री अपने बजट भाषण में तर्क दे रहे हैं कि ''समग्र मांग मुद्रास्फिति का कारण है'', ''खाद्य मुद्रास्फिति ही चिन्ता का विषय है'' और इसीलिए जरूरत है कि ''आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सभी-संभावित कदम उठाए जाएं।'' दूसरे शब्दों में, किताबी भाषा में, मुद्रास्फीति को ''मांग-संचालित'' बताया जा रहा है। वास्तव में ही अद्‌भुत! जबकि कंगाल हो गए देशवासियों के पास प्रतिदिन दोवक्त का खाना जुटाने तक के साधन उपलब्ध नहीं हैं और मांग के अभाव में अर्थव्यवस्था को मंदी जकड़ रही है, 'अर्थशास्त्री' वित्तमंत्री की यह खोज नायाब है और नोबल प्राइज के लिए सिफारिश के काबिल हैं! लेकिन, यही सब कुछ नहीं है। एक ही सांस में वित्तमंत्री कहते हैं कि ''कृषि की बेहतरी जारी है'' और ''2012-13 में कुल खाद्य उत्पादन 25 करोड़ टन से अधिक होगा।'' इसलिए, उत्पादन में कोई घटती नहीं है। तब आपूर्ति में क्या परेशानी है? हमारे 'विद्वान' वित्तमंत्री के पास कोई उत्तर नहीं है। फसल उत्पाद में किसी कमी की वजह से आपूर्ति बाधित नहीं है बल्कि इसकी वजह है जमाखोरी, कालाबाजारी, प्रशासनिक मशीनरी की अन्दरूनी कमियाँ और अनियमितताएं, देशवासियों को भूखा रखते हुए कुछ आइटमों का अंधाधुंध निर्यात और आवश्यक वस्तुओं सहित उपभोक्ता सामानों की कीमतों के उतार-चढ़ाव की बढ़ती सट्टेबाजी। जो भी हो वित्तमंत्री इस मामले में न तो 'चिन्तित' हैं और न ही उन्होंने यह बताया है कि आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनकी पेशकश क्या है।

काले धन पर रोक लगाना–वित्तमंत्री के एजेण्डे पर नहीं है

संबद्ध मुद्दा है घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति को हवा देते हुए बेखौफ विचरण कर रहे भारी काले धन को नियंत्रित करने का। न तो कालेधन के पैदा होने को रोकने या बिना हिसाब के भारी धन के कम से कम एक हिस्से को वसूलने के लिए किसी कदम का लेशमात्र भी उल्लेख बजट में नहीं है। साधारण शब्दों में कहें तो, गुप्त आमदनी या धन जिस पर टैक्स अदा नहीं किया गया काला धन है जो आपराधिक तरीकों के जरिए पैदा हुआ है जैसे धन का गैरकानूनी आदान-प्रदान, आय या सम्पत्ति मूल्य को कम करके बताना, नशीले पदार्थों या हथियारों की तस्करी, घूसखोरी, राजनीतिकों और अफसरशाहों द्वारा ली जाने वाली दलाली इत्यादि इत्यादि। भारी मात्रा का यह काला धन किसी भी आकलन से परे मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, मुद्रास्फीति के दबाव को कई गुना तेज कर रहा है, सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है और अर्थव्यवस्था को विकृत कर रहा है। असल में निरन्तर बढ़ता काला धन समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। यह बताया गया है कि 75 लाख करोड़ रुपए तक का काला धन जो कुल सर्कुलेशन का मात्र एक अंश है, संदिग्ध तरीकों से विदेशों में जमा किया गया है और अधिक गैरकानूनी लाभ बटोरने के लिए भारतीय उद्योगपतियों, राजनीतिकों और अफसरशाहों द्वारा खोले गए व्यक्तिगत खातों में पड़ा है। यदि काले धन की यह भारी मात्रा भारत में वापस लाई जा सके तो 24 घण्टों में पूरे विदेशी कर्ज की अदायगी के बाद भी विदेशी कर्ज से 12 गुना अतिरिक्त धन बच जाएगा जिसे यदि निवेश किया जाए तो केन्द्रीय सरकार के सालाना बजट से ज्यादा ब्याज कमा लेगा। तमाम टैक्सों का खात्मा किया जा सकता है और इस धन का केवल एक छोटा हिस्सा खर्च करके तमाम भारतीयों को भूख के चंगुल से निकाला जा सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सर्वजनीन बनाया जा सकता है, जल संशोधन, साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेण्ट, रिन्युएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी ढाँचागत और देश में सम्बद्ध क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

लेकिन ''सभी मोर्चों पर मुद्रास्फीति का मुकाबला करने'' की बात कहने वाले 'कॉरपोरेट वकील' वित्तमंत्री के एजेण्डे पर काले धन को काबू में करने और पहले से जमा बिना हिसाब के धन को बाहर निकालने के लिए कठोर कदम उठाना नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जीएएआर को टाल देने के अलावा उन्होंने बजट में सर्विस टैक्स न अदा करने वालों के लिए 'वालंटरी कम्पलाएंस एनकरेजमेण्ट स्कीम' की घोषणा भी की है। अन्य बहुत सी चीजें जैसे मॉरिशॅस रूट अपनाने के जरिए टैक्स को चकमा देने के लिए विदेशी निकायों को परोक्ष प्रोत्साहन देना, भारत में निवेश के लिए पहले धन को बाहर जाने देना और फिर घुमा फिरा कर वापस लाने देना ये सभी इस मकसद को पुख्ता करने के लिए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि न तो 1. 76 लाख करोड़ रुपए के 2जी घोटाले का और न ही 10. 67 लाख करोड़ रुपए के कोयला आबंटन घोटाले का कोई जिक्र बजट में किया गया है हालांकि इस मद में सरकारी खजाने को 12.25 लाख करोड़ रुपए तक का संभावित राजस्व घाटा हुआ है। सरकारी खजाने को इतने भारी पैमाने का चुना लगाया जाना वित्तमंत्री के लिए कोई खास बात नहीं है, उनकी सरकार और उनके चाटुकार बढ़ते बजट घाटे पर चिन्ता का दिखावा कर रहे हैं।

सब्सिडी और जन कल्याण में भारी कटौती

स्वाभाविक है कि जब अमीरों, समृद्धों, वारे-न्यारे करने वालों, अपराधियों, ठगों, सटोरियों, पब्लिक फण्ड के लुटेरों, घूसखोरों, जमाखोरों, कालाबाजारियों और निश्चित ही मुनाफा लूटने वाले समृद्धशाली वर्ग और पूँजीपति मालिकों को छोड़ देने को प्रतिज्ञाबद्ध वित्तमंत्री के पास मरे हुए को और मारने तथा लोगों को बढ़ती वित्तीय बर्बरता का शिकार बनाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ''समावेशित विकास के उद्देश्य को हासिल करने के लिए आर्थिक स्पेस पैदा करने और संसाधनों को तलाशने'' के लिए वित्तमंत्री ने सब्सिडी में जबरदस्त कटौती की घोषणा की है। तेल सब्सिडी 96800 करोड़ रुपये से घटाकर 65000 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका मायने है तेल कीमतों को निरन्तर बढ़ाते जाना। तेल कीमतें आवश्यक वस्तुओं के दामों को लगातार बढ़ाती जाएंगी। लेकिन वित्तमंत्री और योजना आयोग के डिप्टी चेयरमेन के मुताबिक यदि कीमतें बढ़ती हैं तो लोग कम ईंधन खरीदेंगे और इस प्रकार तेल आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा की अच्छी-खासी बचत होगी। निस्संदेह अर्थव्यवस्था और किफायतशारी के बारे में कितना बड़ा ज्ञान है। उनके कहने का अर्थ है सिंचाई के लिए पम्प सेटों को चलाने की खातिर गरीब किसान डीजल का इस्तेमाल बन्द कर देंगे, बढ़े हुए बस-रेलवे किराए को वहन करने में असमर्थ मुसाफिर पैदल सफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट लागत में बढ़ोतरी के चलते आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी की वजह से लोग कम खाएंगे और थोड़े वस्त्र पहनेंगे। इस प्रकार, गरीबी की मारी जनता की ''मितव्ययता'' मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाएगी ताकि अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाए हालांकि मंत्रीगण, अफसरशाह, अधिकारीगण अपनी सुख-सुविधाओं, विलासिता और भत्तों के लिए सरकारी खजाने से खुलकर खर्च करना जारी रखेंगे। अत: शोषणमूलक शासक वर्ग के इन सुविधाभोगी ''आर्थिक विशेषज्ञों ने बजट घाटा कम करने का बहाना बना कर ईंधन-तेल, उर्वरकों, खाद पर कुल मिलाकर सब्सिडी 2012-13 में 247854 करोड़ रुपए से घटाकर 220971 करोड़ रुपए कर दी है। ऐसा बताया गया है कि सरकार के मौजूदा प्रोजेक्टिड फिस्कल कॉन्सोलिडेशन को हासिल करने के लिए सब्सिडियों में अनुमानित कटौती 166824 करोड़ रुपए तक होगी। जनकल्याण के लिए किए जाने वाले खर्च में धीरे-धीरे कटौती की नीति के साथ सामंजस्य रखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए अनुदानों में भी व्यापक कटौती की जाएगी। उदाहरण के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए आबंटित 27258 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य सेवा के लिए आबंटित 37330 करोड़ रुपए जरूरत के मुकाबले बहुत ही कम हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए आबंटन इस बार जीडीपी के अनुपात में कम है। आर्थिक सर्वे भी स्वीकारता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत ही कम है।

इसी प्रकार रेलवे किराए में भारी बढ़ोतरी भी आम लोगों पर करारा प्रहार है। हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने रेलवे बजट की आलोचना करते हुए जारी एक संक्षिप्त वक्तव्य में बताया था कि संसद को दरकिनार करते हुए अति गैर जनवादी एक्जीक्युटि लेजिशलेशन रूट के माध्यम से एक महीना पहले यात्री किराए और माल भाड़े में की गई भारी वृद्धि के बाद एक बार फिर किरायों और शुल्कों में बढ़ोतरी के जरिए केन्द्रीय रेल बजट ने देशवासियों को छला है और ईंधन-तेल के दामों में उतार-चढ़ाव के साथ संगति रखते हुए समय-समय पर बढ़ोतरी के साथ-साथ अधिकाधिक पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल का रास्ता अपनाते हुए अंततोगत्वा होने वाले रेलवे के निजीकरण की ओर इशारा किया है।

इस प्रकार साफ है कि जहाँ कॉरपोरेट सैक्टर और अरबपतियों-खरबपतियों को सीमाहीन टैक्स माफी और टैक्स छूट प्रदान करने को विवेकशीलता और वित्तीय सुदृढ़ीकरण का हिस्सा माना जा रहा है, काले धन की उत्पत्ति की ओर से आँखें बंद करके इसे आर्थिक गतिशीलता के रूप में देखा जा रहा है और सट्टेबाजों तथा कीमतों में हेराफेरी करने वालों को बाजार के सहयोगियों के रूप में पनपने दिया जा रहा है वहीं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सब्सिडी को वर्जनीय विलासिता के रूप में देखा जा रहा है। इसे कोई क्या कहे –बदनीयत, शरारत, शैतानी या लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा?

निरन्तर बढ़ता रक्षा बजट

इसी प्रकार मिलिट्री साजोसमान और उपकरणों की खरीद में घोटालों को लेकर एक के बाद एक हुए

(शेष पृष्ठ 5 पर)

केन्द्रीय बजट 2013–14

(पृष्ठ 4 का शेष)

खुलासों के बावजूद वित्तमंत्री ने अति अनुत्पादक रक्षा बजट में 203672 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया जो वित्तीय घाटे का लगभग 40% है। वित्तमंत्री ने ''सदन को'' यह आश्वासन भी दिया कि ''किसी अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के रास्ते में मजबूरियाँ आड़े नहीं आएंगी।'' अफसोस! उत्पीड़ित और बदहाल देशवासियों को कुछ राहत प्रदान के सवाल पर ऐसा कोई आश्वासन देने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की। हम जानते हैं कि निश्चित कारणों से वे ऐसा नहीं कर सकते। यह भी देखा गया कि बजट घोषणा के तुरन्त बाद बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों और टीकाकारों के एक तबके ने मिलिट्री के लिए इतने कम आबंटन की आलोचना की है।

उनके अनुसार, हालांकि हमारी मिलिट्री ताकत को पुख्ता करने की जरूरत है ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ आवश्यक रोकथाम को सुनिश्चित किया जा सके, फिर भी चीन की तुलना में बजटीय आबंटन फीके पड़ जाते हैं। यह नोट करना अति आवश्यक है कि जहाँ देश के लोग शांतिपूर्ण तरीकों और आपसी बातचीत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ सीमा और अन्य तमाम विवादास्पद मुद्दों का न्यायसंगत निपटारा चाहते हैं, वहीं भारतीय शासक वर्ग अपने तुच्छ वर्ग स्वार्थ में जानबूझकर टालमटोल कर रहा है और तमाम ऐसे मामलों को लटकाए हुए है। उल्टे, यह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध मानसिकता भड़का रहा है और लोगों को यकीन दिला रहा है कि देश पर बाहरी आक्रमण का खतरा है और इसीलिए मिलिट्री पावर को और भी उन्नत करने की जरूरत है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। इतिहास इस तथ्य की तसदीक करता है कि यदि वास्तव में ही देश किसी बाहरी खतरे का सामना करता है तो दमनकारी पूँजीवादी राजसत्ता की भाड़े की सेना नहीं बल्कि चट्टान सरीखी एकता पर आधारित, सच्चे देशभक्ति के जज्बे से सराबोर और उच्च तथा उत्तम विचारधारा से प्रेरित देश के लोग ही प्रभावकारी प्रतिरोध प्रदान करेंगे और देश की सार्वभौमता की रक्षा करेंगे। अतः व्यापक जनता के मुँह का निवाला छीन कर पूँजीवादी भारत में मिलिट्री बजट बढ़ाने का लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह नितांत जन-विरोधी कदम है। असल में, शासक भारतीय एकाधिकारी पूँजीपति न केवल एशिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्जेय मिलिट्री सुपर-पॉवर के रूप में उभरने की चाह रखने के चलते सार्वजनिक खर्च में कटौती करके अपने शस्त्र भण्डार को निरन्तर पुख्ता कर रहे हैं और आधुनिक बना रहे हैं। धंसती जा रही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए भी भारतीय शासक वर्ग के पास अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक सैन्यीकरण का रास्ता अपनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लोगों को भूखे और बढ़ती कीमतों के बाझ तले दबाकर रखते हुए रक्षा बजट में नियमित बढ़ोतरी के पीछे यही कारण है। लेकिन मौजूदा संसद में एसयूसीआई(सी) के एकमात्र सांसद के सिवाय और किसी ने इस नापाक इरादे का पर्दाफाश नहीं किया बल्कि छद्म-मार्क्सवादियों सहित पूरे विपक्ष द्वारा इसे उचित ठहराया गया।

लोगों को वित्तमंत्री के ''तोहफे''

''विद्वान'' वित्तमंत्री और बुर्जुआ अर्थशास्त्री तथा वित्तीय विश्लेषक इससे नाराज हो जा सकते हैं। वे दावा कर सकते हैं कि ''कौन कहता है कि वित्तमंत्री ने लोगों के विशाल तबके को लाभों के दायरे से बाहर रखा है?'' वे चिल्ला सकते हैं, ''वित्तीय समावेश को कारगर करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव हैं।'' अतः बजट में उन अनूठी चीजों पर हमें ध्यान देना है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने दावा किया है कि ''वित्तीय समावेश ने तीव्र डग भरे हैं। तमाम अनुसूचित कमर्शियल बैंक और तमाम आरआरबी कोर बैंकिंग सोल्युशन्स (सीबीएस) पर तथा इलेक्ट्रोनिक पैमेण्ट सिस्टमों (एनईएफटी और आर टी जी एस) पर हैं। कुछ कॉ-ऑपरेटिव बैंकों सहित तमाम अन्य बैंकों को 31.12.2013 तक सीबीएस और ई-पेमेण्ट प्रणालियों पर लाने के लिए हम आरबीआई के साथ काम कर रहे हैं।'' इसका अर्थ है बैंक ऑपरेशनों के आधुनिकीकरण से ''समावेशी विकास'' का उद्देश्य हासिल हो जाएगा, कोई बात नहीं भले ही अधभूखे, अध-नंगे करोड़ों कंगाल जो जनसंख्या का प्रमुख हिस्सा हैं उनके पास बैंकों में रखने के लिए फूटी-कौड़ी भी न हो।

जहाँ तक रोजगार पैदा करने का सवाल है महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्पलाएमेण्ट गारण्टी स्कीम (मनरेगा) के तहत आबंटन उतना ही है जितना पिछले साल के बजट में था लेकिन घोषित उद्देश्य के लिए फण्डों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही आबंटन बढ़ाने के लिए कोई माँग की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय का आंकड़ा दर्शाता है कि 2009-10 में मनरेगा ने 284 करोड़ कार्य-दिवसों का काम पैदा किया था। अगले साल यह 257 करोड़ था और 2011-12 में और भी घट कर यह 216 करोड़ रह गया। क्या इसकी वजह यह है कि ग्रामीण गरीबों को रोजगार की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। जबकि स्कीम का घोषित उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और बेरोजगारों के लिए जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, अब इसे केवल तभी इस्तेमाल किया जा रहा है जब प्रशासन महसूस करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्ति पैदा करने वाले रोजगारों की जरूरत है जैसे भूमि उत्पादकता और जल उपलब्धता को बढ़ाना। अतः मनरेगा के तहत कार्य मौसमी व विशिष्ट रूप से अवसर-आधारित हो गया है और इसलिए अपने घोषित उद्देश्य से भटक गया है। भ्रष्ट प्रशासन-पंचायतों-पुलिस-अपराधियों-शासक पार्टी के गुण्डों और नेताओं के भ्रष्ट गठजोड़ द्वारा मनरेगा फण्डों के गबन की खबरें आई हैं। ऐसे ही असल लाभार्थियों को उचित मजूरी न देना भी साफ तौर से उजागर हुआ है। फिर भी, वित्तमंत्री महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। उनका रोजगार पैदा करने का नुस्खा अब उद्योगों में लाभप्रद आवश्यकता आधारित पारिश्रमिक पर काम मुहैया करना नहीं बल्कि कम आय और नगण्य सामाजिक सुरक्षा वाले अस्थाई असंगठित निर्माण कार्य में लगाने के लिए है। लेकिन हम जानते हैं कि यदि वास्तव में ही सरकार चाहे तो जैसा आजादी के तुरन्त बाद की अवधि में किया गया था ओएनजीसी, एनटीपीसी की तर्ज पर सरकारी क्षेत्र के तहत दक्षतापूर्वक संचालित और अधिक उद्योग स्थापित करके अच्छी खासी संख्या में रोजगार पैदा कर सकती है लेकिन इस रास्ते का अनुसरण न करके सरकार विनिवेश कर इन्हें पूँजीपतियों द्वारा निगल जाने की इजाजत दे रही है।

इसके अलावा कुछ कमाल के करतब हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं! '' महिलाओं को निरापद और सुरक्षित रखने, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए'', वित्तमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के ''निर्भया'' फण्ड का सुझाव दिया है बिना कुछ बताए कि इसके इस्तेमाल का दायरा और तरीका क्या होगा। क्या ऐसा है कि उन्होंने अंदाजा लगाया है कि महिलाओं पर अपराध और हिंसा बढ़ेगी और इसलिए पीड़ितों को खैरात देने के लिए फण्ड की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में ही विचित्र! सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बैंक खोलना भी इतना ही हास्यास्पद है। इसको समझने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है कि बढ़ते बलात्कारों, यौन हमलों और महिलाओं पर अन्य अत्याचारों के असल कारण से ध्यान बंटाने और जघन्य दिल्ली गैंग रेप काण्ड को केन्द्र कर उभर रहे आन्दोलन पर ठण्डा पानी डालने का यह चालाकी भरा पैंतरा है।

लोगों के एक भी मुद्दे को नहीं छुआ गया

इस प्रकार यह साफ जाहिर हो गया है कि जहाँ गरीबों और सर्वहाराओं की बहुत बड़ी संख्या बढ़ती महंगाई, तीव्र बेरोजगारी, अधिकाधिक रोजगार हानि, बढ़ती भुखमरी, जानलेवा भूख और वास्तव में ही न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा की अनुपलब्धता की मार झेल रही है वहीं शासक दमनकारी पूँजीवाद के वर्ग स्वार्थ की सेवादारी में अति चालाक शिल्पकार की धूर्तता का परिचय देते हुए केन्द्रीय वित्तमंत्री ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो केवल औद्योगिक घरानों, कॉरपोरेट सैक्टर, बड़े व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरतों और चाहतों की ही पूर्ती करता है। इस वास्तविकता को छिपाने के लिए चापलूस अर्थशास्त्री, स्तम्भकार और अफसरशाह 'आर्थिक मजबूरी' का धूम्रपट पैदा करने में लगे हुए हैं और डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के एकमात्र उपचारात्मक उपाय के तौर पर 'कठोर सुधारों' का नुस्खा पेश कर रहे हैं। यह भी नोट करने लायक तथ्य है कि जहाँ वास्तविकता को छिपाने के लिए भारी भरकम जुमलों और शब्दाडम्बरों की आड़ में तमाम तरह की बकवास, उन्मादी और उल जलूल बातें करते हुए सरकार और इसके ताबेदार पण्डितों द्वारा निर्देशित, संचालित अर्थव्यवस्था को डॉवांडोल हालत में ला खड़ा किया है। वहीं कंगालीग्रस्त आम लोगों से कहा जा रहा है कि वे इसकी मार झेलें। कहीं लोग इनकी आज्ञा का पालन करने से मना न कर दें इसलिए उनको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ झांसेबाज स्कीमों को पेश करना जरूरी समझा गया। अतः आम आदमी के लिए इस बजट से कुछ भी उम्मीद नहीं है। सिवाय उपहास, वंचना और बेरहम आर्थिक दमन की एक नई खुराक के।

पूँजीवाद की घिनौनी साजिश नाकाम करें

यह स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि बजट कोई रामबाण नहीं है न ही इसमें लोगों की बढ़ती मुसीबतों को कम करने का लेशमात्र भी प्रयास किया गया है। उल्टे यह बदनीयत से भरा है, इसमें नितांत झूठ और छलावे की भरमार है। यह एक वर्ग का बजट है, कॉरपोरेट सैक्टर का बजट है, दमनकारी शासक एकाधिकारियों का बजट है, शोषणमूलक वित्तीय पूँजी का बजट है और इसीलिए, असल में यह लोगों के जीवन और जीविका पर निर्लज्ज हमला है। कॉमरेड शिवदास घोष के प्रबुद्धकारी विचारों से निर्देशित एसयूसीआई(सी) के सिवाय देश में दूसरी और कोई पार्टी नहीं है जो पूँजीवाद की इस घृणित साजिश के बारे में लोगों को जागरूक कर सके और समाधान का रास्ता सुझा सके। कांग्रेस, भाजपा व अन्य क्षेत्रीय बुर्जुआ, पेटी-बुर्जुआ पार्टियों जैसी शासक पूँजीवाद के प्रति प्रतिबद्ध पार्टियों और ताकतों से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वे तथाकथित सुधार एजेण्डे के पीछे छिपे शासक वर्ग के घृणित खेल को सामने नहीं लाएंगी, बल्कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी तरफदारी ही करेंगी सिवाय इसके कि लोग दिखावे के लिए यदा-कदा चुनिन्दा विरोध का कुछ दिखावा करें और वोटों के सिलसिले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी रहें। उदाहरण के तौर पर, हालांकि तथाकथित आर्थिक उदारीकरण कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में 1990 के दशक के दौरान लागू किया गया था। इसके बाद सत्तासीन हुई भाजपा सरकार ने भी इसी एजेण्डे को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि रिफोर्म पैकेज के कई आइटमों को जिन्हें अब लागू किया जा रहा है जैसे खुदरा व्यापार में सीधे विदेशी निवेश(एफडीआई) को भाजपा शासनकाल में शुरू किया गया था। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि सीपीआई(एम), सीपीआई जैसे स्वयंभू मार्क्सवादी वामपंथी भी उसी नौका पर सवार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद को सरकारी नीतियों के सबसे बड़े आलोचक के रूप में पेश कर रहे हैं। एक के बाद इन जनविरोधी सुधारों के लिए सरकार की भर्त्सना करते हुए भी सीपीआई(एम), सीपीआई इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके निशाने पर सिर्फ शासक पार्टी है न कि पूँजीवाद, मानो सत्तासीन पार्टी तमाम चीजें अपने आप ही कर रही हो और सरकार का परिवर्तन लोगों को सारी राहत प्रदान कर देगा। अपने आप को प्रदर्शित करते हुए सत्ता हथियाने की खातिर एक दूसरे से होड़ करना किसी भी चुनावी पार्टी की खासियत है। असल में, इनमें से बहुत से सुधार जैसे एफडीआई को बुलाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करना, आम आदमी पर अतिरिक्त सैस और टैक्स थोपना जबकि औद्योगिक घरानों को भरपूर रियायतें, राहत व छूट प्रदान करना, महत्वपूर्ण सैक्टरों का निजीकरण-व्यापारीकरण करना इत्यादि छद्म-मार्क्सवादियों और उनके सहयोगियों द्वारा तब लागू किया गया था जब वे कुछ राज्यों में सत्ता में थे। क्योंकि बुर्जुआ दलों की तरह, ये स्वयंभू मार्क्सवादी भी धन और सत्ता के लिए शासक वर्ग को खुश करने की दौड़ में रहे हैं। इसलिए ये इस पर भी कड़ी नजर रखते हैं कि उत्पीड़ित लोगों का रोष-आक्रोश कभी पूँजीवाद-विरोध की दिशा में संचालित न हो और न ही विनाशकारी आर्थिक सुधारों के खिलाफ कोई सचेत, सतत, सशक्त, संगठित आन्दोलन विकसित हो सके। छद्म-मार्क्सवादियों का यह विश्वासघात शासक वर्ग और इसके भरोसेमंद दायरे को सक्षम बना रहा है कि वे भूमण्डलीकरण-उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के जरिये बेरहम पूँजीवादी दमन की चक्की में लोगों को पीस रहे हैं। एसयूसीआई(सी) लोगों से यह समझने की अपील करती है कि यह बजट न केवल जन-विरोधी है बल्कि प्राणघातक आर्थिक हमले की शुरूआत का ब्लू प्रिण्ट है। इसलिए, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे अपनी जायज मांगों को हासिल करने के लिए सशक्त संगठित आन्दोलन का निर्माण करें और आन्दोलन के दबाव के तहत पूँजीवादी आर्थिक सुधारों के इस हमले का प्रतिरोध करें तथा पूँजीपति-परस्त ताकतों को अलग-थलग कर दें जो उनका जीना दूभर कर देने के लिए शासक वर्ग के जी-हजूरियों के रूप में काम कर रही हैं। ●●

अफजल गुरू की फांसी और कुछ प्रश्न

8 फरवरी को तिहाड़ जेल में कश्मीरी युवक अफजल गुरू की फाँसी को केन्द्र कर विभिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। मुकदमा सही था कि नहीं, केवल एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा आपरेशन चलाना संभव था कि नहीं उसको फाँसी देना ठीक रहा कि नहीं इत्यादि बहुत तरह के सवालों को लेकर ही देश में बहस छिड़ी हुई है। यह बहस चले। लेकिन जिसको लेकर कोई बहस नहीं हो सकती वह है, अफजल गुरू की माँ, पत्नी, पुत्र और अन्य सम्बद्ध लोगों के प्रति देश तथा सरकार का घोर अमानवीय व निष्ठुर आचरण। अफजल गुरू की फाँसी के आदेश को क्रियान्वित करने को लेकर बरती गई अत्यन्त गोपनीयता की एक व्याख्या सरकार ने दी है। लेकिन वह कतई संतोषजनक नहीं है।

कानून के मुताबिक परिवार को समय रहते खबर देने, मृत्युदण्ड को क्रियान्वित किए जाने से पहले कम से कम एक बार जरूर रिश्तेदारों को मिलने देने और मृतदेह को अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करने से क्या अपने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समझने वाला भारत देश एकदम टूट जाता! यह सिर्फ सरकार की सदाशयता को प्रदर्शित करने का सवाल नहीं है बल्कि इसके साथ हर किसी कैदी के मानव अधिकार का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अफजल गुरू की पत्नी तबस्सुम ने भारत की नागरिक होने के नाते चाहा था कि कम से कम लाश को उनके सुपर्द किया जाए। इसको लेकर गृहमंत्री का उत्तर भी अत्यन्त अमानवीय है। उन्होंने कहा था कि परिवार के द्वारा आवेदन किए जाने पर वे अफजल गुरू द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को वापस दिया जाए या नहीं और जेल के अन्दर जहाँ उसे दफनाया गया वह कब्र देखने दी जाए कि नहीं इसके बारे में सोचेंगे। एक शोकसंतप्त परिवार जिसके प्रियजन को सरकार ने अभी फाँसी दी है उनके इतने से आवेदन को भी क्या सरकार सरासर मंजूर नहीं कर सकती थी?

संसद हमले में अफजल गुरू को परोक्ष प्रमाणों के आधार पर दोषी ठहराया गया था। मुकदमा शुरू होने के साथ ही साथ 'अपराधी' घोषित कर देने की वजह से इस बारे में भी कुछ सवाल हैं। अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए अफजल को कोई पसंद का वकील नहीं करने दिया गया। फलतः सर्वोच्च कानूनी सहायता उसे नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में जितनों को भी गिरफ्तार किया था उनमें से एक का मृत्युदण्ड रद्द करके 10 साल जेल की सजा हुई थी। अन्य लोगों पर निचली अदालत में मृत्युदण्ड दिए जाने पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। संसद भवन पर हमले जैसी घटना को केवल एक व्यक्ति द्वारा अंजाम देना संभव है कि नहीं इस प्रश्न का उठना क्या बिल्कुल अस्वाभाविक है? और भी कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। 13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन पर हमले के समय हमलावर गाड़ी पर लाल बत्ती तथा गृह मंत्रालय का स्टीकर लगा कर आए थे। यह कैसे संभव हो सका? देश की राजधानी में ऐसी एक घटना घट गई और गुप्तचरों को उसकी कोई भनक तक कैसे नहीं लगी! सम्बन्धित खुफिया अफसरों और गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ इसके लिए क्या कदम उठाए गए इसकी जानकारी तो देश के लोगों को होनी चाहिए! सबसे बड़ा प्रश्न उठा है परिवार के प्रति आचरण को लेकर। अफजल के परिवार को फाँसी की खबर स्पीड पोस्ट के जरिये दी गई जो उनकी फांसी के दो दिन बाद मिली। आज की तीव्रतम संचार व्यवस्था के युग में जो अत्यन्त हास्यास्पद है। गृहमंत्री ने कहा है कि परिवार को पहले खबर देने से वह खबर फैल जाती। फलस्वरूप लोग विक्षुब्ध हो जाते। इसी वजह से खबर नहीं दी गई। लेकिन लोगों में इसी गोपनीयता को लेकर रोष बढ़ गया है। कश्मीर के लोगों के सामने सरकार का कौन सा चेहरा उजागर हुआ है? उन्होंने देखा कि देश की सरकार उनपर तनिक भी भरोसा नहीं करती है। यहाँ तक कि दिल्ली के विशिष्ट पत्रकार इफ्तिकार गिलानी और उनकी पत्नी को 9 दिसम्बर को पुलिस ने पकड़ कर पाँच घण्टे बिठाए रखा, उनके स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों को भी दिन भर शयन कक्ष में ताला बन्द करके पुलिस ने अटकाए रखा। प्रेस काऊंसिल के चेयरमेन मार्कण्डेय काटजू द्वारा दोषी पुलिस वालों को सजा देने की मांग किये जाने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। इफ्तिकार का एकमात्र कसूर यह है कि वे कश्मीरी हैं और हुरियत कान्फ्रेंस के नेता गिलानी के दामाद हैं। किसी 'अभियुक्त' व्यक्ति या राजनैतिक नेता का घनिष्ठ आत्मीय होने से क्या वह अपराधी हो जाता है? यह कैसा जनतन्त्र? यह घोर स्वेच्छाचार है।

अफजल गुरू का जीवन भी इस बात की पुष्टि करता है। अफजल एमबीबीएस के एक मेधावी छात्र थे। कश्मीर की परिस्थिति ने उसे अलगाववादी आन्दोलन की तरफ धकेल दिया। लेकिन कुछ दिनों के अन्दर ही पाकिस्तानपंथी उग्रवादी गुटों के बारे में उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने बीएसएफ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अफजल स्वस्थ स्वाभाविक जीवन की तरफ लौटना चाह रहे थे। पूर्व उग्रवादी होने के अपराध में सेनावाहिनी और बीएसएफ के कुछ अफसर घूस लेने के लिए उस पर बारबार अकथनीय अत्याचार करते थे। अफजल और उनकी पत्नी अपना सब कुछ बेच कर भी उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए। 21 अक्टूबर 2004 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने कश्मीर टाइम्स के पत्रकार को इसका मर्मस्पर्शी विवरण दिया था। उन्होंने सेना और बीएसएफ के जिन तमाम अफसरों के नाम लेकर आरोप लगाया था उनको तो कोई भी सजा नहीं दी गई है। अफजल गुरू ने खुद भी संसद हमले का अभियुक्त होने के बाद जांचकर्ताओं के सामने और 2005 में एक साक्षात्कार में बताया था कि एक पुलिस अफसर ने किस प्रकार दिल्ली में मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति के लिए घर किराए पर लेने के लिए उसे मजबूर किया था। वरना उसके परिवार को मार डालने की धमकी दी गई थी। इसके बाद उसे कश्मीर वापस लौट जाने के लिए कहा गया था। इसी बीच संसद भवन पर हमले की घटना घट गई। मोहम्मद नाम के व्यक्ति द्वारा खरीदी गई गाड़ी संसद हमले में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने कश्मीर से ही अफजल गुरू को गिरफ्तार किया था। अफजल का आरोप था इस व्यक्ति एवं सम्बन्धित अफसर का नाम तथा उनके बारे में सविस्तार बताने के बावजूद पुलिस ने धमकी दी–यह बात अदालत में या पत्रकारों को बताने से उसके परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। (आनन्दबाजार पत्रिका, 10 फरवरी 2013)। लेकिन इस संगीन इल्जाम का कोई भी जवाब देशवासियों को नहीं दिया गया।

मुख्य धारा के संवाद माध्यमों ने ही सवाल उठाया है कि 8 साल लटकते रहने के बाद अचानक ऐसा क्या घट गया कि जिससे अकस्मात और फटाफट तथा नाटकीय गोपनीयता से अफजल की फाँसी को क्रियान्वित करना पड़ा? उन्होंने ही उत्तर दिया है, वोट बड़ी बला है। महंगाई, निरन्तर बढ़ती बेकारी, आर्थिक मंदी, नारी उत्पीड़न में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन निम्नतम स्तर पर है। इन सब का धक्का सम्भालने में कांग्रेस सरकार दिशाहीन हो गई है। उनका संसदीय विकल्प भाजपा जानती है कि इन हालात में किसी आर्थिक खुशहाली के नारे से उनकी दाल नहीं गलेगी। कांग्रेस के घोटालों–भ्रष्टाचार की तरफ भी वे उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप के चलते भाजपा को अपने अध्यक्ष को बदलना पड़ा। लोग जान गए हैं कि भाजपा भी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई है। इसीलिए भाजपा–आरएसएस फिर से देश के वोटरों को उग्र हिन्दुत्ववाद के नशे में मदहोश कर देना चाहती है। इसी वजह से वे नरेन्द्र मोदी का नाम सामने ला रहे हैं। मोदी के बहुत बड़े पैरोकार भी जानते हैं कि गुजरात का विकास पुरुष कह कर कितना ही ढोल पीटा जाए मोदी का एक ही परिचय जनमानस में घर किए हुए है कि वह हिन्दुत्ववादी राजनीति के पोस्टरबॉय हैं। अल्पसंख्यकों के जनसंहार का प्रतीक है। 2014 के लोकसभा चुनावों पर टकटकी लगाए हुए अल्पसंख्यकों के प्रति विद्वेष का जहर भरा पिटारा फिर नए सिरे से खोल देना चाहती है भाजपा। कांग्रेस यहीं पर दिशाहीन है। क्योंकि विकल्प के रूप में कुछ अच्छा देने की क्षमता इस पार्टी की नहीं है। अतः एक समय जिस तरह राजीव गाँधी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अन्दर मंदिर स्थापना का शिलान्यास करके खुद को 'हिन्दुत्व का ध्वजधारी' साबित करना चाहा था, इस बार अचानक अफजल गुरू के खिलाफ फाँसी का आदेश क्रियान्वित करके कांग्रेस ने भाजपा के साथ हिन्दुत्ववाद की प्रतियोगिता में उतरने की परिकल्पना की है। इसीलिए किसी व्यक्ति को (भले ही अपराधी हो) इस तरह चरम गोपनीयता से परिवार को जानकारी दिये बिना फाँसी देनी होगी! यह तो घोर बर्बरता है!

भवन निर्माण श्रमिकों का सोनीपत जिला सम्मेलन सम्पन्न

सोनीपत (हरियाणा): भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर मजदूरों की समस्याओं को लेकर 31 मार्च को भवन निर्माण कारीगर–मजदूर यूनियन सम्बन्धित ऑल इण्डिया यूटीयूसी की तरफ से यहाँ कुम्हार धर्मशाला में पहला जिला सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉ. इन्द्र सिंह ने की।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड रामफल सुहाग ने सम्मेलन में उपस्थित कारीगर मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा घोषित सुविधाओं का नाममात्र का लाभ मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने में ही सरकार द्वारा डोमिसाईल जैसी कई नाजायज शर्तें थोपी जा रही हैं। इसलिए स्कीम का सदस्य बनाना ही कठिन बना दिया गया है। ऊपर से, भ्रष्टाचार के चलते इसके रुपयों को दलाल और अधिकारी खा जाते हैं। मिस्त्री–मजदूरों को साल में कुछ माह ही काम मिल पाता है। बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चन्द पूँजीपतियों के हित में काम कर रही है। आज मजदूरों को अपने संगठन मजबूत करके आन्दोलन की ताकत से ही अपने अधिकार हासिल करने होंगे।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड रामफल सुहाग

यूनियन के जिला सम्मेलन में एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के कॉ. बलवान सिंह, भवन निर्माण कारीगर–मजदूर यूनियन के कॉ. बलबीर सिंह खटक, कॉ. शिवचरण व कॉ. रामफल आदि ने भी अपने विचार रखे।

महिला दिवस पर सभा

इन्दोर (म.प्र.): 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां स्थानीय महिला पोलीटैक्निक कॉलेज में सभा करके मनाया गया। सभा को महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय कमेटी की कार्यकारिणी सदस्या कॉ. रचना अग्रवाल व इन्दोर जिला प्रभारी कॉ. अर्शी खान ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन महिला पोलीटैक्निक कॉलेज की पुनीत उप्पल ने किया। काफी संख्या में छात्राएं सभा में शामिल हुई।

आरोन : 8 मार्च अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर में महिला सांस्कृतिक संगठन इकाई आरोन के द्वारा एक सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन महिलाओं के अधिकार और देश के सांस्कृतिक माहौल के परिप्रेक्ष्य में रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में गुना से आई संगठन की जिला सचिव निधि श्रीवास्तव व संगठन की नगर सचिव शमा परवीन ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुये 8 मार्च का ऐतिहासिक महत्व बताया।

भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव शहादत दिवस

(पृष्ठ 3 का शेष)

व चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर उ.प्र. के माननीय राज्यपाल को भेजा गया।

बलिया (उ.प्र.): ऑल इण्डिया डीवाईओ ब्लॉक कमेटी की ओर से शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू शहीद दिवस पर 23 मार्च को एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की शुरूआत शहीदों के चित्र पर पुष्प भेंट कर तथा क्रान्तिकारी गीतों के साथ हुआ। एआईकेकेएमएस के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. बेचन अली मुख्य वक्ता थे। सभा को मुख्य रूप से कॉ. रामप्रवेश, संजय सिंह, अनिल कुमार, विक्रम सिंह, गणेश प्रसाद, विरेन्द्र यादव, कमलेश कुमार आदि ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री खूबलाल यादव एवं संचालन एआईडीवाईओ जिला सचिव कॉ. मुन्ना शर्मा ने किया।

दुर्ग (छ.गढ़): 23 मार्च को आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी योद्धा, शहीद-ए-आजम भगत सिंह का शहीद दिवस ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. एवं ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. द्वारा मनोनाइट चर्च दुर्ग के सामने पूरे सम्मान के साथ मनाया गया व क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्षों को लेकर सभा की गई। सभा की शुरूआत शहीद भगत सिंह के फोटो पर माल्यार्पण के साथ हुई। सभा को सम्बोधित करते हुए ऑल इण्डिया डीवाईओ के राज्य इंचार्ज कॉ. विश्वजीत हारोडे ने कहा कि आज भी क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्ष हमारे लिए प्रेरणीय है। ऑल इण्डिया डीएसओ के दुर्ग जिला इंचार्ज कॉ. महेन्द्र साहू ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि हर युग में प्रगतिशील छात्र-युवाओं ने संगठित होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए अपनी जान न्यौछावर की। इसका जीवंत उदाहरण महान क्रान्तिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव है। कार्यक्रम का संचालन कॉ. आत्मा राम साहू द्वारा किया गया।

डुमरिया (पूर्वी सिंहभूम): 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के 82वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक रैली की गई। रैली डुमरिया बस स्टैण्ड से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे गाँव में घूमी और फिर वापिस बस स्टैण्ड पहुँचकर खुली सभा में तब्दील हो गई। शहीद वेदी पर माल्यार्पण के बाद वक्ताओं ने सभा में अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता के रूप में एआईडीएसओ के सभाध्यक्ष कॉ. पवन लुथिया ने सभा को सम्बोधित किया।

राँची (झारखण्ड): एआईडीएसओ की राँची जिला कमेटी की ओर से 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू का शहीदी दिवस सैक्टर 2, ध्रुव, राँची में मनाया गया। पहले उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने उन महान क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्ष पर चर्चा की और उनसे सीख लेने का आह्वान किया। परिचर्चा में एसयूसीआई(सी) के झारखण्ड राज्य सचिव कॉ. रबिन समाजपति, पार्टी की राज्य कमेटी सदस्या और एआईएमएसएस की राज्य सचिव कॉ. केया डे भी उपस्थित थी।

सागर (म.प्र.): एआईडीएसओ एव एआईडीवाईओ के तत्वावधान में 23 मार्च को चौरसिया धर्मशाला के पास तिली वार्ड सगर में शहीद-ए-आजम भगतसिंह शहादत दिवस पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य वक्ता कॉ. रामअवतार शर्मा थे। सभा को अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य कॉ. मंजीत पटेल ने सम्बोधित किया। अध्यक्षता अशोक कुशवाहा ने की एवं अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन कॉ. गणेश पटेल ने किया। कार्यक्रम का समापन शहीदों की याद में नारों एवं गीतों के साथ किया गया।

इंदौर (म.प्र.): शहीद भगत सिंह विचार मंच के तत्वावधान में 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू का शहीदी दिवस स्थानीय जगदाले कॉलेज, छावनी चौराहा व मूसाखेड़ी टेम्पो स्टैण्ड पर शिद्दत से मनाया गया। इस दिन जगदाले कॉलेज में इन क्रान्तिकारियों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व कॉलेज प्राध्यापिका श्रीमती शिखा त्रिवेदी द्वारा उनके विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताई गई। मंच की सदस्या श्रीमती अर्शी खान ने समाज की समस्याओं से लड़ने के लिए शहीद भगतसिंह व अन्य क्रान्तिकारियों के विचारों को आदर्श के रूप में अपनाने पर जोर दिया।

मंच के द्वारा शाम 5 बजे मधुमिलन चौराहे से छावनी चौराहे तक श्रद्धांजली रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथियों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में मूसाखेड़ी टेम्पो स्टैण्ड पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मंच के सदस्यों अर्शी खान, सक्षम पटवा, सौम्या पवार व संतोष मीना के द्वारा बात रखी गई। काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों द्वारा भी क्रान्तिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई।

भिवानी (हरियाणा): 22 मार्च को एआईडीएसओ व एआईडीवाईओ की ओर से शहीदों की याद में दिनोद गेट स्थित चेतराम प्रजापति धर्मशाला से शुरू कर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मशाल जुलूस निकाला। एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के नगर कमेटी अध्यक्ष कॉ. रूपेश ने शहीदों के जीवन-संघर्ष से सीख लेने और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। 23 मार्च को एआईडीएसओ और एआईडीवाईओ की ओर से शहीद-ए-आजम भगतसिंह सुखदेव व राजगुरू का शहादत दिवस नेहरू पार्क में मनाया गया। इसमें छात्र संगठन के हरियाणा के प्रभारी कॉ. चंचल घोष मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर छात्रों ने देशभक्ति, क्रान्तिकारी गीत, कविताएं प्रस्तुत किए। वहीं तोशाम में शहीदी दिवस पर एआईडीएसओ और भगत सिंह एकता संगठन ने जुलूस निकाला और नुक्कड़ सभाएं की। इनकी अध्यक्षता छात्र संगठन के नेता भीम सिंह ने की और छात्र नेता अजय ने मंच का संचालन किया। एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव कॉ. रामफल ने बतौर मुख्य अतिथि क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्ष से विद्यार्थियों और नौजवानों को अवगत कराया। उन्होंने आजादी आन्दोलन के महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी, साहस, कर्तव्यपरायणता, सामाजिक जिम्मेदारी बोध जैसे गुणों से सीख लेने, हर तरह के जुल्म व अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया।

रेवाड़ी (हरियाणा): शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के 82वें बलिदान दिवस पर एआईडीवाईओ द्वारा राव तुलाराम पार्क में स्मृति सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी प्रो. अनिरुद्ध यादव ने की। मुख्य वक्तव्य संगठन के जिला अध्यक्ष कॉ. शेर सिंह ने रखा। मंच का संचालन जिला सचिव कॉ. अनिल निमोठ ने किया। जिला कमेटी सदस्य कॉ. नरेश कुमार एवं एसयूसीआई(सी) की जिला कमेटी सदस्य कॉ. रामकुमार ने भी बात रखी। **मीरपुर** में एआईडीवाईओ तथा शहीद भगत सिंह यादगार समिति के तत्वावधान में स्मृति सभा का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

सोनीपत (हरियाणा): आजादी आन्दोलन की समझौताहीन धारा के सशक्त प्रतिनिधि शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के शहादत दिवस पर एआईडीएसओ, एआईकेकेएमएस एवं एआईयूटीयूसी द्वारा कुम्हार धर्मशाला में स्मृति सभा आयोजित की गई। सभा को अन्य वक्ताओं के अलावा एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी ने सम्बोधित किया।

नारनौल (हरियाणा): 23 मार्च को रैस्ट हाऊस के सामने एआईडीएसओ, एआईकेकेएमएस, और एआईयूटीयूसी द्वारा शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के शहीद दिवस पर आयोजित जनसभा की अध्यक्षता किसान नेता कामरेड बलबीर सिंह ने की। सभा को एसयूसीआई (सी) के जिला इन्चार्ज कॉ. ओमप्रकाश, एआईयूटीयूसी के कॉ. शमशेर सिंह, सुभाषचन्द, कर्मचारी नेता हरि सिंह मुलौदिया, सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सिंह, महेशदत्त शर्मा, भीम सैन व बिजेन्द्र सिंह आदि वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ शहीद भगत सिंह का संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

गुड़गाँव (हरियाणा): एआईडीवाईओ द्वारा शहीद-ए-आजम भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू के बलिदान दिवस पर प्रभातफेरी का आयोजन किया गया। यह प्रभातफेरी गुड़गाँव के विभिन्न क्षेत्रों, न्यू रेलवे रोड व स्वतंत्रता सेनानी दया किशन कटारिया मार्ग से होते हुए सैनी भवन पर संपन्न हुई। प्रभातफेरी का नेतृत्व आर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष कॉ. बलवान सिंह व संगठन के जिला सचिव कॉ. राजेश कुमार ने किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 5 April, 2013

स्विस महिला से बर्बर बलात्कार की ऑल इण्डिया महिला सांस्कतिक संगठन द्वारा कड़ी निन्दा

स्विस महिला से हुए बर्बर बलात्कार की कड़ी निन्दा करते हुए ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की महासचिव डॉ. एच.जी. जयालक्ष्मी ने 17 मार्च 2013 को जारी बयान में कहा:

''एआईएमएसएस की अखिल भारतीय कमेटी मध्य प्रदेश के दतिया जिला में 15 मार्च को हुए उस काण्ड से बेहद दु:खी है और इसकी कड़ी निन्दा करती है जिसमें 8 लोगों के एक समूह ने स्विस दम्पत्ति पर हमला किया, 39 वर्षीय महिला से दरिन्दगी से बलात्कार किया और उनका पैसा और कीमती सामान लूट लिया। जैसे कि मीडिया में खबर छपी है, डीआईजी (चम्बल रेंज) डी.के. आर्य ने कहा है कि हमलावरों ने पुरुष को बांध दिया और महिला से सामूहिक बलात्कार किया। मेडिकल जाँच के बाद डाक्टरों ने बलात्कार होने की अनौपचारिक तौर पर पुष्टि की बताते हैं।

यह बड़ी शर्म की बात है कि मीडिया में महिलाओं के अश्लील चित्रण, नशाखोरी और शराबखोरी की बुराई और साथ ही अपराधियों को सजा न मिलने के कारण जिसने अपराध करने के लिए उनके हौंसले बढ़ा दिए हैं, आए दिन हर घड़ी ऐसे शर्मनाक काण्ड हो रहे हैं। देश के समस्त प्रबुद्ध लोगों की ओर से एआईएमएसएस मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता है कि अपराधियों की तुरन्त धरपकड़ करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे।

छात्रा के साथ दुष्कर्म के खिलाफ कैण्डल मार्च

राँची (झारखण्ड): सिकिदिरी थाना क्षेत्र के अनगडा इलाके में एक कॉलेज की छात्रा के साथ चार व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। छात्रा को न्याय न मिलने पर उसने खुदकुशी कर ली। इसके विरोध में 21 मार्च को एआईडीएसओ, एआईएमएसएस और एआईडीवाईओ के संयुक्त प्रयास से राँची के फिरायलाल चौक पर कैण्डल मार्च निकाला गया। इसमें भारी संख्या में छात्र, छात्राएं, युवा एवं महिलाएं शामिल हुए। इसके साथ ही इस घटना के विरोध में राँची समेत पूरे राज्य भर में आन्दोलन का ज्वार फूट पड़ा। आन्दोलन के दबाव के कारण पुलिस-प्रशासन को यह केस गम्भीरता से लेना पड़ा और आन्दोलन के अगले ही दिन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

घाटशिला (झारखण्ड): राँची में लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में 23 मार्च को एआईडीएसओ के तत्वावधान में एक मानव श्रंखला बनाई गई और सभा की गई। इसमें सैकड़ों छात्राओं ने शिरकत की। सभा को कॉ. कनाई बारीक ने सम्बोधित किया।

महिलाओं पर बढ़ते अपराध, नशाखोरी व अश्लीलता के खिलाफ नागरिक सम्मेलन

शालीमार बाग-पीतमपुरा (दिल्ली): महिलाओं पर बढ़ते अपराध, नशाखोरी व प्रचार माध्यमों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ 17 मार्च को शालीमार बाग में नागरिक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में महिलाओं पर बढ़ते अपराध, नशाखोरी तथा अश्लीलता के खिलाफ श्रीमती वृंदा दास द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव पारित हुआ। सभा को अरूप भाई, शशि वधवा, मीनू तलवार, शालीमार बाग-पीतमपुरा पार्टी इंचार्ज कॉ. प्रकाश देवी तथा मुख्य वक्ता के तौर पर एस.यू.सी.आई. (सी) राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉ. हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। सम्मेलन में महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसे क्षेत्रीय नागरिकों ने काफी सराहा। सभा के आखिर में धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती सुमन चौहान ने रखा। सम्मेलन में सुमन चौहान को अध्यक्ष तथा ज्योति भूषण को सचिव समेत 18 सदस्यीय कमेटी का चुनाव हुआ। सभा का संचालन शालीमार बाग की इंचार्ज श्रीमती नीतू खन्ना ने किया। 24 मार्च को बुराड़ी इकाई की ओर से सतीश शर्मा की वाटिका, सत्य विहार में जनसम्मेलन का आयोजन किया गया।

कॉमरेड किम जोंग उन के नाम आईएसीसी का संदेश

एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य और इण्टरनेशल एंटी-इम्पीरियलिस्ट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (आईएसीसी) के महासचिव कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने 2 अप्रैल को डीपीआरके (उत्तर कोरिया) के सुप्रीम नेता कॉमरेड किम जोंग उन को निम्नलिखित संदेश भेजा :

प्रिय कॉमरेड किम जोंग उन,

अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी परमाणु क्षमता वाले स्टैल्थ बमवर्षक विमानों को दक्षिण कोरिया में तैनात करके कारियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाने की साज़िश की दुनिया के शान्तिकामी लोग बार-बार निन्दा कर रहे हैं। डीपीआरके की सरकार गिराने, समाजवादी राष्ट्र को ढहाने और समाजवाद का नामोनिशान मिटा डालने के दृढ़प्रतिज्ञ इरादे से डीपीआरके पर हमला करने की यह दक्षिण कोरिया के लिए योजना है। डीपीआरके की राजसत्ता और कोरियाई जनता द्वारा समाजवाद और सुरक्षा तथा किसी भी बाहरी आक्रमण के बहादुराना विरोध के प्रति पूरी दुनिया के सभी शान्तिकामी लोगों की एकजुटता है। अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई आक्रमण से आत्मरक्षा के लिए और अगर हमला हो तो हर तरह के साधन अपनाने के लिए डीपीआरके के सम्प्रभु अधिकारों का हम समर्थन करते हैं। इस प्रकार के किसी भी आक्रमण की कार्रवाई के अंजाम की पूरी जिम्मेदारी पूर्णत: दक्षिण कोरियाई और संयुक्त राज्य अमेरिकी हुकूमत पर आयद होगी। दुनिया की जनता समेत हम भी यही बात दोहराते हैं कि डीपीआरके के संघर्ष में हम उनके साथ खड़े हैं।

शिक्षा बचाओ कमिटी की ओर से परिचर्चा का आयोजन

जमशेदपुर (झारखंड) : विगत 17 मार्च को ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी, झारखंड राज्य शाखा की ओर से जमशेदपुर में 'ज्वलंत शैक्षणिक समस्याएं और आंदोलन की रूपरेखा' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर मित्रेश्वर ने की। इस परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया कमिटी से श्री देवाशीष राय उपस्थित थे। उन्होंने विस्तार से सरकार की वर्तमान विनाशकारी शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। इसके अलावा परिचर्चा में मुख्य रूप से डॉ. शालिग्राम यादव (पूर्व चेयरमैन, झारखंड एकेडेमिक काउंसिल), डॉ बी पी केशरी (जनजातीय भाषा के रांची वि.वि.विभागीय अध्यक्ष), डॉ. सुभाष गुप्ता (प्रोफेसर, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर), श्री नंद कुमार उन्मन (विशिष्ट कवि व साहित्यकार), डॉ. सुबोध सिंह, प्रोफेसर इंदल कुमार , शिक्षक नेता रंजीत कुईला व सुनील ठाकुर सहित कई प्रख्यात शिक्षाविदों व बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। परिचर्चा के दौरान पूरे देश की और खासकर झारखंड की बदहाल शिक्षा पर गंभीर चिंता जतायी गयी और शिक्षा बचाओ आंदोलन तेज करने के लिए कई सुझाव दिये गये। सभी ने एकस्वर में आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

अंत में कमिटी के झारखंड राज्य सचिव श्री सुमित राय ने सर्वभारतीय स्तर पर अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ कमिटी की ओर से चलाये जा रहे आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए झारखंड में भी आंदोलन को और ताकतवर बनाने की अपील की।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यूईए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com; sarvaharadrishtikon@gmail.com